वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी0 चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और चालू वर्ष के पहले छः महीनों (अप्रैल-सितम्बर) जिसके विदेश व्यापार के आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान आयात-निर्यात का निष्पदन निम्नलिखित है :-

(मिलियन अमरीकी डालर)

	निर्यात	आयात
1993-94	22237	23306
1994-95	26330	28654
1995-96 (अप्रैल-सितम्बर)	14685	17065

अन0=अनन्तिम

(ख) से (घ) चालू वर्ष (1995-96) में निर्यात लक्ष्य में अमरीकी डालर के रूप में लगभग 20% वृद्धि का संकेत हैं। आयात के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है और व्यापारी, उद्योग तथा अन्य संबंधित संस्थानों के परामर्श से निर्यात बढ़ाने के उपाय किये जाते हैं। सरकार नीति और क्रियाविधियों को निर्यात के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही है। निर्यात के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही है। निर्यात के सवंर्धन के लिये किये गए उपायों में निम्नलिखित उपायों का उल्लेख किया जा सकता हैं। निर्यात आयात-नीति और क्रियाविधियों का सरलीकरण, निर्यात उतपादन बढ़ाना, कार्य कुशलता तथा प्रतिस्पर्धात्मकताओं में वृद्धि करना, गुणवत्ता सुधार और तकनीकी अन्नयन पर बल देना, बुनियादी सुविधाओं में सुधार तथा निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिया रूप से भागीदार बनाना। चालू वष्र में एक वार्षि कार्य योजना तैयार की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात संवर्धन के लिये वस्तु विशिष्ट एवं देश विशिष्ट उपाय शामिल हैं। आयात आवश्यकतानुसार किये जाते हैं।

कोयला उत्पादन का लक्ष्य

755. **श्री अनंतराय देवशंकर दवे :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान कोयले के उत्पादन के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) गुजरात सहित अन्य राज्यों की कोयले की मांग को किस सीमा तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1995-96 के लिये समग्र अखिल भारतीय कोयले का उत्पादन लक्ष्य 274.50 मिलियन अन निर्धारित किया गया है। कंपनी-वार उत्पादन ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

	(मिलियन टन में)
कोल इंडिया लि0	241.00
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि0	28.00
अन्य	5.50
जोड़:	274.50

(ग) कोयले की मांग राज्यवार निर्धारित नहीं की जाती है। इसका निर्धारण समग्र देश के लिये उद्योग-वार तथा क्षेत्र-वार किया जाता है। कोयले की वर्ष 1995-96 के लिये प्रक्षिप्त अखिल भारतीय मांग 288 मिलियन टन हैं। मांग तथा उत्पादन के बीच के अंतराल को 7.50 मिलियन टन स्टाक की निकासी करके तथा 6 मिलियन टन कोककर कोयले का आयात करके पूरा किया जाएगा।

Misutilisation of Funds in Super Bazar

756. SHRI GOVIND RAM MIRI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of misutilisation of funds in Super Bazar;

(b) if so, whether the Statutory Audit Department has reviewed the Super Bazar accounts and the working of said organisation particularly of textiles and furniture departments;

(c) if so, whether some objections have been raised in this regard and if so, the details thereof alongwith the measures taken/being taken thereon;

(d) whether the super bazar is incurring huge losses every year; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM (SHRI VINOD SHARMA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

(d) No, Sir. Super Bazar has reported that it is in profit since 1972-73.

(e) Docs not arise.

Implementation of Child Labour Laws

757. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether State Governments are sending their reports regarding implementation of child labour laws; and

(b) if so, the details of the States which have not implemented child labour laws so far and the remedial steps taken to implement the child labour taws in each such State?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) Apart from enforcing the various provisions made under the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986, there are protective provisions in various labour laws as well, such as the Factories Act, 1948 the Mines Act, 1952, the Motor Transport (Workers) Act, 1961 etc. The approach of the Government is to implement all (he child-related provisions of the laws in a harmonious fashion. Enforcement machinery at the Central and State level exist to enforce the provisions of these Acts. Employers are liable to be prosecuted for violations of the provisions of the Acts. Enforcement personnel are being given special training for better enforcement of these laws. The number of cases detected for violation of the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 during the last three years are as under:—

Year	No. of Violations
1992-93	1884
1993-94	1814
1994-95*	2166

'Complied on the basis of information received from 20 States/UTs so far.

Role Played by Labour Tribunal in Times of India Strike

758. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the role played by the Labour Tribunal in the recent strike by the staff of Times of India in Delhi in September, 1995;

(b) the conditions under which the strike was withdrawn;

(c) whether any staff was victimised;

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Annual Plan Outlay for Punjab

759. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what is the outlay sanctioned'for the annual plan for the year 1995-96 in respect of the State of Punjab;

(b) what targets have been set up for agricultural and industrial production in the annual plan for Punjab for the year 1995-96; and

(c) what is the sector wise plan outlay made in the annual plan in the State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a)